आज़ादी का अमृत महोत्सव

साप्ताहिक सूचना पत्र

(दिनांक 17.09.2023 से 23.09.2023)

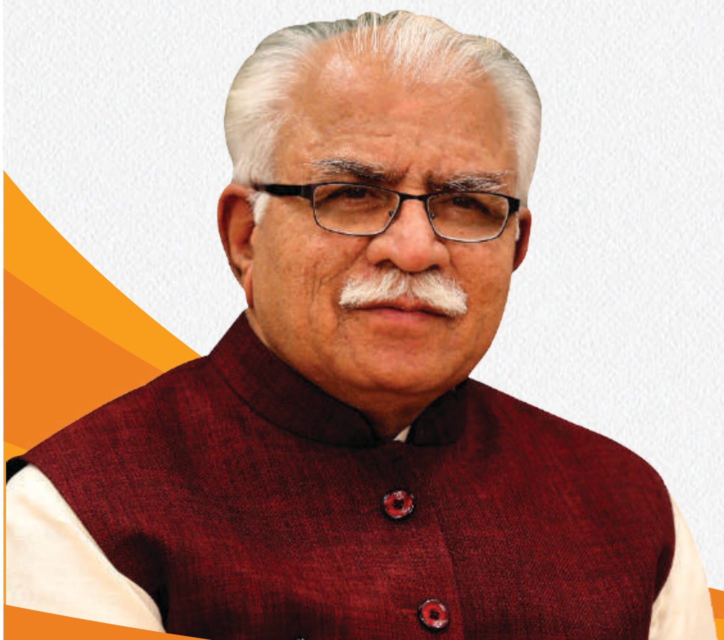

भारतीय जनता पार्टी
हरियाणा

सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम पहुंची साइक्लोथॉन यात्रा

(दिनांक 17.09.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी आज रविवार को सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम के मुख्य द्वार पर साइक्लोथॉन यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले यात्रा में भाग ले रहे प्रतिभागियों व आमजन को संबोधित कर कहा कि आज की साइक्लोथॉन में जनभागीदारी ने वर्ष 2019 में आयोजित मैराथन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने नशा मुक्त हरियाणा अभियान के लक्ष्य के साथ प्रदेश का दौरा कर रही साइक्लोथॉन को आज सिरसा में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा जिस प्रकार से ड्रग्स की गिरफ्त में फंसता चला जा रहा है, यह चिंता का विषय है और यह साइक्लोथॉन यात्रा जागरूकता पैदा करने में सार्थक साबित हो रही है। इस

यात्रा में स्कूलों, महाविद्यालयों व अन्य शैक्षणिक संस्थानों से भाग ले रहे साइक्लिस्ट का धन्यवाद किया। उल्लेखनीय है कि एक सितंबर को करनाल से साइक्लोथॉन यात्रा शुरू की गई थी और यह अब तक 15 जिलों में ड्रग फ्री हरियाणा का संदेश पहुंचा चुकी है और 25 सितंबर को यह यात्रा करनाल में सम्पन्न होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए प्रेरणा का विषय है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है। पूरे देश में लोग सेवा कार्यों के माध्यम से जनता की सेवा कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की दीर्घ आयु की कामना कर रहे है। उन्होंने प्रार्थना की कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसी प्रकार प्रधानसेवक बनकर देश की निरंतर सेवा करते रहे हैं तथा लोगों में प्रेरणा जागृत करें। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का भारत बनाने के लिए हरियाणा सरकार लगातार केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 17

सितंबर का दिन एक और कारण से भी खास है, आज भगवान विश्वकर्मा का जन्म दिवस है। उन्होंने देश व प्रदेश के श्रमिकों, मजदूरों, कारीगरों व कामगारों को बधाई व शुभकामनाएं दी। साइक्लोथॉन यात्रा में जनभागीदारी का आंकड़ा अब तक दो लाख के पार हो चुका है। आने वाले दिनों में यह यात्रा फतेहाबाद, रतिया, टोहाना, उकलाना, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर होते हुए करनाल में सम्पन्न होगी। उन्होंने कहा कि साइक्लोथॉन यात्रा नशा मुक्ति के संदेश के अपने उद्देश्य में सफल हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ड्रग फ्री हरियाणा अभियान को सफल बनाने के लिए तीन मुख्य कदम है। नशे का सेवन करने वाले व्यक्तियों को डिएडिक्शन सेंटर (नशा मुक्ति केंद्रों) में पहुंचाना ताकि वे नशा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें। अभिभावक अपने बच्चों को संभालें, यदि युवाओं का जीवन बचेगा तो समाज, प्रदेश व देश सुरक्षित होगा।

विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कार्यक्रम

(दिनांक 17.09.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने पलवल जिला में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर श्रमिकों के कल्याणार्थ अनेक घोषणाएं की। उन्होंने भगवान श्री विश्वकर्मा जयंती तथा माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस पर प्रदेश व देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि अभी तक बेटों व बेटियों को छात्रवृत्ति राशि में अंतर रहता था, लेकिन बेटों व बेटियों को एक समान मानते हुए आज से निर्णय लिया गया है कि सभी प्रकार की छात्रवृतियों की राशि दोनों के लिए एक समान होगी। उन्होंने औद्योगिक श्रमिकों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में अभूतपूर्व बढ़ोतरी करने की घोषणा की। वर्तमान में छात्रवृत्ति की राशि, जो 5000 रुपये से शुरू होकर 16000 रुपये तक दी जाती थी, वह अब 10000 रुपये से शुरू

होकर 21000 रुपये तक दी जायेगी। उन्होंने श्रमिकों की स्नातक स्तर में शिक्षा प्राप्त कर रही बेटियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी प्रदान करने के लिए 50 हजार रुपये की राशि देने की घोषणा की। इसी प्रकार, श्रमिकों को साइकिल खरीदने हेतु 3000 रुपये की राशि बढ़ाकर 5000 रुपये करने, महिला श्रमिकों को सिलाई मशीन खरीदने हेतु 3500 रुपये की राशि बढ़ाकर 4500 रुपये करने की भी घोषणा की। इसके अलावा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्रोनिक बीमारी होने पर श्रमिकों को स्वास्थ्यप्रद खान–पान हेतु 2000 रुपये प्रति माह दिये जाने की भी घोषणा की। इसके अलावा, फतेहाबाद तथा जिला गुरुग्राम के हरसरू, कादीपुर, वजीराबाद में ई. एस. आई. डिस्पेंसरी स्थापित की जाएगी तथा हरियाणा राज्य की सभी ई.एस.आई. डिस्पैंसरियों में ई.सी.जी. सुविधायें उपलब्ध करवाई जायेंगी।

उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि परिवार का पालन पोषण करने के लिए

काम की तलाश में श्रमिकों को एक नगर से दूसरे नगर जाना पड़ता है, इसलिए उनकी सुविधा हेतु पहले चरण में फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत व यमुनानगर में प्रत्येक जिले में 500–500 फ्लैट उपलब्ध करवाये जायेंगे। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की ओर से गुरू शिष्य कौशल सम्मान योजना शुरू की जा रही है। इसका उद्देश्य अनौपचारिक क्षेत्र के 25,000 शिल्पकारों, कारीगरों और श्रमिकों जैसे प्लंबर, बढ़ई, राजमिस्त्री आदि की कौशल क्षमता को पहचानना, प्रमाणित करना और उन्हें दक्ष गुरु के रूप में पहचान दिलवाना है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

शहीद मेजर आशीष जी को श्रृद्धांजलि

(दिनांक 17.09.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पानीपत पहुंचकर देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले शहीद मेजर आशीष को पानीपत स्थित उनके आवास श्रृद्धांजलि अर्पित की और उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया और कहा कि परिवार को सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। साथ ही शहीद मेजर की पत्नी को योग्यता के अनुसार नौकरी भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मेजर आशीष ने मां भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। दुख की इस घड़ी में सरकार परिवार के साथ है। उन्होंने कहा कि मेजर आशीष का नाम हमेशा अमर रहेगा।

साप्ताहिक सूचना पत्र

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ

(दिनांक 17.09.2023)

प्रभाव : माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज अपना 73वां जन्म दिवस भगवान विश्वकर्मा को समर्पित करते हुए देश के कामगारों, श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सहित कई योजनाओं शुभारंभ किया।

इस योजना से जरूरतमंद और गरीब वर्ग को लोगों के लोगों को लाभ मिलेगा। योजना के तहत पारंपरिक कार्य करने वाले शिल्पकारों, कारीगरों को प्रशिक्षण, ऋण सुविधा सहित अन्य कई प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार जताते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान श्री विश्वकर्मा की जयंती पर श्रमिकों के लिए अनेक योजनाओं की शुरुआत कर सही मायने में श्रमेव जयते को चरितार्थ किया है। भगवान श्री विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर हरियाणा में राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को अनूठे रूप से मनाया गया और राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि श्रम ही जीवन है, अगर कोई व्यक्ति श्रम करना छोड़ देगा, आलसी हो जाएगा तो उसके जीवन में कभी भी खुशहाली नहीं आ सकती है।

हरियाणा में 25 प्रतिशत श्रमिक संगठित क्षेत्र में हैं और 75 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र के हैं। राज्य सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए भी लगातार काम कर रही है। प्रदेश में दो श्रम कल्याण बोर्ड बनाए गए हैं। इनके माध्यम से श्रमिकों को विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान किए जा रहे हैं।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रमिकों का आह्वान किया कि उनके कल्याण हेतु केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें।

महर्षि मारकंडेश्वर ट्रस्ट द्वारा आयोजित मेगा हेल्थ कैंप

(दिनांक 17.09.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंबाला में माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर सामाजिक सरोकार के रूप में सेवा कार्य हेतु महर्षि मारकंडेश्वर ट्रस्ट द्वारा एम.एम. सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में आयोजित मेगा हेल्थ कैंप में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर कहा कि आज के युग में यदि कोई गरीबों का मसीहा है तो वे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। उन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई हैं, चाहे स्वास्थ्य, मकान, शिक्षा, रोजगार इत्यादि योजनाएं हों, इन सब प्रयासों के फलस्वरूप

साप्ताहिक सूचना पत्र

गरीबों व जरूरतमंदों को बहुत लाभ हुआ है। भूतकाल में केवल गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता था, लेकिन इतने वर्षों में गरीबी को दूर करने के कोई इंतजाम नहीं किए गए, लेकिन पिछले 9 वर्षों में गरीबी दूर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितने विकासात्मक कार्य हुए हैं, उतने शायद ही पहले कभी हुए हैं।

उन्होंने कहा कि इस मेगा हेल्थ कैंप में 8000 से 10,000 लोगों का हेल्थ चौकअप 700 से 800 डॉक्टर्स की टीम द्वारा किया गया। उन्होंने नागरिकों का आह्वान करते हुए कहा कि नागरिकों को जीवन में स्वस्थ जीवनशैली को अपनाना चाहिए। इसलिए लोगों को सही खान–पान की आदत और नियमित योग करने की आदत को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गरीबों को महंगे इलाज की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना चलाई है। हरियाणा सरकार ने इस योजना का विस्तार करते हुए चिरायु हरियाणा योजना आरंभ की है। इसके तहत 1.80 लाख रुपये सालाना आय वाले परिवारों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त ईलाज की सुविधा मिलती है। अब राज्य सरकार ने एक और निर्णय लिया है जिससे 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपये सालाना आय वाले परिवार भी मात्र 125 रुपये प्रति माह के प्रीमियम देकर 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए अधिक से अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि डॉक्टरों की संख्या बढ़ सके। जिला स्तर और ब्लॉक स्तर तक भी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, ताकि एक भी व्यक्ति अस्वस्थ न रहे। सरकार ग्राम स्तर तक वेलनेस सेंटर बनाने पर काम कर रही है। निरोगी हरियाणा योजना का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक का हेल्थ चौकअप करना, अब तक 40 लाख लोगों का टेस्ट किया जा चुका।

साप्ताहिक सूचना पत्र

अंबाला में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन

(दिनांक 18.09.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अम्बाला शहर के एस.ए. जैन महा विद्यालय के सभागार में आयोजित जनसंवाद में कहा कि शहरों के रेजिडेंशियल इलाकों में कुछ लोगों ने कमर्शियल बिल्डिंग व शोरूम बना लिए हैं, ऐसे में जो लोग निर्माण कर चुके हैं, उनके लिए सरकार जल्द से जल्द एक पॉलिसी लेकर आई जाएगी।

जिसके तहत उन रेजिडेंशियल इलाकों में जो इलाका कमर्शियल हो चुका है, उस इलाके को कमर्शियल कर दिया जाएगा। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां अभी भी रेजिडेंशियल इलाकों को कर्मिशयल किया जा रहा है, उन्हें नोटिस जारी किए जाएं। यदि इसके बाद भी कोई नहीं मानें तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

जन संवाद कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर निगम के एसई विवेक गिल से शहर में रेजिडेंशियल

इलाकों में हो रहे कमर्शियल निर्माण पर सवाल किया तो, वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।

इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसई विवेक गिल का तबादला करने के आदेश दिए। वहीं कॉलोनियों को अप्रूव करने के विषय पर उन्होंने कहा कि पिछले दिनों प्रदेश में 450 कॉलोनियों को अप्रूव किया है। अभी तक 1800 कॉलोनियां अनअप्रूव हैं। जल्द ही प्रदेश की 400 और कॉलोनियों को भी अप्रूव किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अम्बाला शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के सवाल पर निर्देश दिए कि अम्बाला शहर में जल्द ही इंटिग्रेटिड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) बनाया जाएगा। इसका पैसा सरकार देगी। गुरुग्राम, करनाल की तर्ज पर यहां भी इंटिग्रेटिड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बने, ताकि ट्रैफिक व अपराधियों पर और पैनी नजर रखी जा सके। उन्होंने जिला उपायुक्त को निर्देश दिए कि शहर का सर्वे करवाया जाए, जहां–जहां सीसीटीवी नहीं है, वहां सीसीटीवी लगाने की व्यवस्था की जाए। शहर की मार्किट में दुकानदार, अनाज मंडी में आढ़ती और बाजार में नगर निगम कैमरे लगाए।

इन कैमरों को पुलिस इंटिग्रेडिट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से कंट्रोल करे। जनसंवाद के दौरान उन्होंने कहा कि पहले शहरों व ग्रामीण क्षेत्र में अपने मन मुताबिक विकास कार्यों के लिए ग्रांट दी जाती थी, लेकिन अब हमने तय किया है कि आबादी के हिसाब से ग्रांट दी जाएगी। जनसंवाद के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लोगों की तत्काल पेंशन बनवाई। इसके अतिरिक्त वार्ड–12 और 15 में कम्यूनिटी सेंटर की मांग पर उन्होंने अधिकारियों को फिजिब्लिटी चौक करने के निर्देश दिए।

मध्य प्रदेश के सुरखी में आयोजित जन आशीर्वाद यात्रा में शिरकत करना

(दिनांक 18.09.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज मध्य प्रदेश के सुरखी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश आज विकसित राज्य की दिशा में बढ़ा है। आज जनता हमारी सरकार पर भरोसा दिखा रही है और समाज का हर वर्ग सरकार की कार्यप्रणाली से संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की यह धरती वीरों व दानियों की धरती है, जिन्होंने सदैव मुगलों और देशविरोधी ताकतों को परास्त किया है। आज यहां आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में रोजगार पैदा हों, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 50 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण, वंचितों व जरूरतमंदों के

साप्ताहिक सूचना पत्र

आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, राज्य सरकार केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को भी ज्यों का त्यों लागू कर जनता को लाभ प्रदान कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि हमने 5–एस शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वाभिमान, सुरक्षा और स्वावलंबन पर जोर दिया है और थ्री–सी यानी करप्शन, क्राइम और कास्ट से जुड़ी राजनीति पर हमने गहरी चोट की है। सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने नागरिकों को पारदर्शी शासन मुहैया करवाया है और पात्र व्यक्तियों को सभी सुविधाएं देने के लिए परिवार पहचान पत्र जैसी अनूठी योजना शुरू की है। इस एक दस्तावेज से सभी नागरिकों को घर बैठे ही सरकारी योजनाओं व सुविधाओं का लाभ ऑनलाइन तरीके से मिल रहा है। आज देश के कई राज्य परिवार पहचान पत्र का अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता इसी तरह भाजपा सरकार की नीतियों तथा विचारधारा में भरोसा दिखाएगी और निश्चित रूप से एक बार फिर यहां हमारी जीत होगी।

साप्ताहिक सूचना पत्र

फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) की चौथी बैठक

(दिनांक 20.09.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) की चौथी बैठक की अध्यक्षता कर कहा कि जेवर एयरपोर्ट आने से फरीदाबाद व पलवल जिला में विकास की नयी संभावनाएं खुलीं हैं।

ऐसे में जेवर के साथ लगते हरियाणा के फरीदाबाद व पलवल जिलों का सुनियोजित विकास हो इसके लिए यमुना क्षेत्र को कण्ट्रोल एरिया घोषित कर नया मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। बैठक में एफएमडीए के माध्यम से फरीदाबाद शहर के विकास को गति देने के लिए वर्ष 2023–24 के लिए कुल 878.23 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गयी। बैठक में वर्ष 2031 तक भविष्य की जनसंख्या वृद्धि और संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकताओं की कल्पना करते हुए शहर के बुनियादी ढांचे में सुधार, नागरिक सेवाओं को बढ़ाने और बेहतर पर्यावरण में योगदान देने के लिए तैयार की गई प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी।

एफएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री ए. श्रीनिवास द्वारा विकास का एजेंडा प्रस्तुत किया गया जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहर के उत्थान और

साप्ताहिक सूचना पत्र

बड़े पैमाने पर जनता के लाभ के लिए मंजूरी प्रदान कर दी। फरीदाबाद के भविष्य के दृष्टिकोण और विजन के साथ एफएमडीए ने शहर में 2031 तक अनुमानित जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत विकास योजना विकसित की है।

फरीदाबाद विकास योजना–2031 के अनुसार पूरे फरीदाबाद शहर की वर्तमान और संभावित आबादी के लिए थोक पेयजल की आपूर्ति के लिए मास्टर प्लान एफएमडीए द्वारा तैयार किया गया है। वर्तमान में, फरीदाबाद में पानी की उपलब्धता 330 एमएलडी है और एफएमडीए द्वारा 12 नए रैनी वेल्स का निर्माण कार्य चल रहा है जिससे आपूर्ति क्षमता 450 एमएलडी तक पहुंच जाएगी। बैठक में अतिरिक्त 22 रैनी वेल्स, 70 ट्यूबवेलों और बूस्टिंग स्टेशनों के निर्माण द्वारा वर्ष 2031 के लिए जल आपूर्ति को 450 एमएलडी से बढ़ाकर 700 एमएलडी करने का प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त 294.15 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से बड़खल और एनआईटी निर्वाचन क्षेत्र में जल आपूर्ति के पूरक के लिए गांव बसंतपुर के राजस्व संपदा में पांच रैनी वेल्स की स्थापना के लिए प्रशासनिक मंजूरी भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अनुमोदित की गई।

ग्रेटर फरीदाबाद में आगरा नहर के साथ लगी 20 किमी लंबी सड़क पे दो अतिरिक्त लेन के निर्माण और मौजूदा दो–लेन के सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर इस मार्ग के माध्यम सेए यात्रियों को दिल्ली, नोएडा और मेरठ, बुलंदशहर या यमुना एक्सप्रेसवे के साथ–साथ फरीदाबाद–जेवर एयरपोर्ट रोड तक पहुंच में सुधार होगा। सेक्टर 77, 78, 83, 84 और 89 के साथ–साथ ग्रेटर फरीदाबाद के गांव खेड़ी कलां, भूपानी और फरीदपुर को जोड़ने वाली खेड़ी कलां बाईपास रोड के 75 मीटर लंबे अधूरे हिस्से के निर्माण का प्रस्ताव भी बैठक में रखा गया इसमें किसानों से जमीन की खरीद के बाद इस

परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा। फरीदाबाद में सड़क नेटवर्क और कनेक्टिविटी में सुधार एफएमडीए के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और हमें कुछ प्रमुख विकास परियोजनाओं पर मंजूरी मिल गई है, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा।

शहर में सीसीटीवी निगरानी के दायरे को मजबूत करनेए सुरक्षा उपायों को बढ़ाने और राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों, सड़कों और शहरी शहर क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण को फरीदाबाद में विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर लगभग 1009 कैमरा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया जिसे मंजूरी दे दी गयी है। इस परियोजना में लगभग 566 सीसीटीवी कैमरे, 48 स्पीड कैमरे, 100 बॉडी वियरेबल कैमरे, 260 ऑटोमेटिक नंबर–प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) कैमरे और 25 रेड लाइट वॉयलेशन डिटेक्शन (आरएलवीडी) कैमरों की स्थापना शामिल होगी, फरीदाबाद में अपराध और यातायात उल्लंघन के कृत्यों को रोकने के लिए करीब 60 करोड़ रुपये की लागत से क्रियान्वित किया जाएगा।

केंद्र सरकार से अमृत 2 योजना के तहत 1494 करोड़ रूपये प्राप्त हुए हैं। इनमें से 370 करोड़ रूपये फरीदाबाद शहर को दिए जाएँगे। वहीं ईडीसी से मिले 560.8 करोड़ रूपये भी शहर के विकास पर खर्च होंगे। सरकार द्वारा एफएमडीए को शहर के सार्वजनिक परिवहन के लिए 50 नयी सीएनजी बसें दी जाएंगी। इसके अलावा 100 नयी ई–बसों का प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है।

‘मोदी–फ्रॉम विजन टू रियलिटी’ पुस्तक का विमोचन

(दिनांक 20.09.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बुधवार को दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय के आडिटोरियम में आयोजित ‘मोदी–फ्रॉम विजन टू रियलिटी’ शीर्षक वाली पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बिताएं समय का उल्लेख किया और कहा कि आज पुस्तक विमोचन का यह विशेष अवसर है क्योंकि इस पुस्तक के पात्र माननीय प्रधानमंत्री और उनका व्यक्तित्व बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में यही बात रहती है कि देश पहले, बाकि सब बाद में आता है। उन्होंने देश के साथ अपने आप को आत्मसात कर लिया है और देश की संस्कृति व इतिहास को पूरे विश्व में फैलाया है। यह पुस्तक सेवानिवृत आईपीएस अधिकारी श्री आर के पचनंदा, जो वर्तमान में

साप्ताहिक सूचना पत्र

हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन हैं, द्वारा सम्पादित की गई है। पुस्तक में कई लेखकों ने अपने लेख दिए है जिनमें बताया गया है कि किस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को बदला है और अपने विजन को वास्तविक रूप दिया है। इसमें कोविड–19 के दौरान विषम परिस्थितियों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुशलतापूर्वक देश का नेतृत्व करके उस विपदा से देश को बाहर लाने, उनके शासनकाल में अपनाये गये आर्थिक सुधारों के वर्णन के साथ–साथ जी–20 शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा निभाई गई अहम भूमिका का उल्लेख किया गया है।

भारत की अध्यक्षता में आयोजित जी–20 शिखर सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रतिभागी देशों को ऐसे समय में राह दिखाई है जब पूरा विश्व कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है। इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में देश के 14वें राष्ट्रपति रहे श्री रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

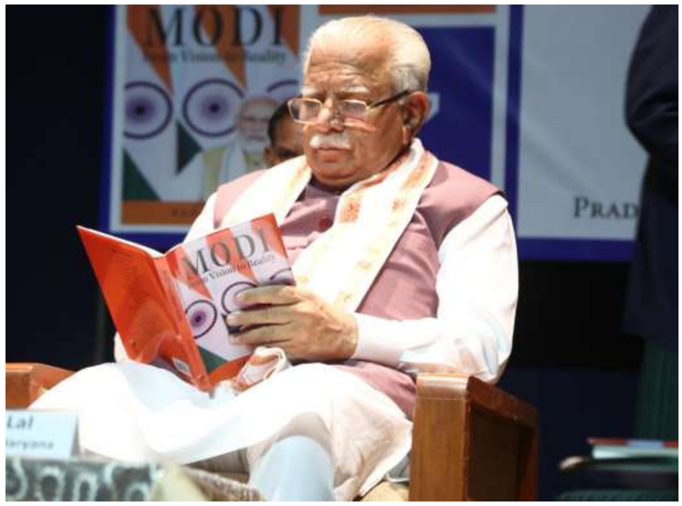

यह पुस्तक माननीय प्रधानमंत्री जी के जीवन चरित्र, विचार, विजन, उपलब्धियां, उनसे मिली प्रेरणा आदि पर लिखी गई है। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक को पढ़ते समय पाठक को ऐसा लगेगा कि जैसे हम उन घटनाओं को देख रहे है, जिनका वर्णन किया गया है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उन्हें काम करने का अवसर मिला। पुस्तक के प्रकाशक राजन आर्य ने पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, माननीय मुख्यमंत्री जी और पुस्तक के संपादक आर के पचनंदा को श्रीमद् भगवत गीता भेंट कर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम का मंच संचालन नलिन कोहली ने किया।

साप्ताहिक सूचना पत्र

प्राइमरी टीचर्स (पीआरटी) की अंतरजिला स्थानांतरण प्रक्रिया पूर्ण

(दिनांक 21.09.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में शिक्षकों के स्थानांतरण में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए बनाई गई ऑनलाइन स्थानांतरण नीति बेहद कारगर सिद्ध हो रही है।

शिक्षकों को अपने चुने हुए विकल्पों में से पसंदीदा स्थान मिल रहे हैं, जिससे वे संतुष्ट है और पठन पाठन का कार्य और अधिक कुशलता से हो रहा है। इसी कड़ी में अब सरकार द्वारा 2004 बैच के प्राइमरी टीचर्स (पीआरटी) की अंतरजिला स्थानांतरण प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, जिसमें 92 प्रतिशत अध्यापकों को उनकी पहली पसंद का जिला मिला है, जो एक ऐतिहासिक कदम है।

राज्य में शिक्षा के स्तर को सुधारने व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार निरंतर बेहतर प्रयास कर रही है। इसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मौलिक शिक्षा निदेशालय ने 2004 बैच के प्राइमरी टीचर्स (पीआरटी) के लिए अंतर जिला स्थानांतरण अभियान शुरू किया था।

इसमें विभिन्न जिलों से 324 पीआरटी ने स्वेच्छा से आवेदन किया था। इन 324 शिक्षकों को वरीयता अनुसार 21 जिलों का विकल्प भरने को कहा गया था। स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद 92 प्रतिशत शिक्षकों को उनकी पहली पसंद का जिला, 7 प्रतिशत शिक्षकों को दूसरी पसंद का जिला और 1 प्रतिशत शिक्षकों को तीसरी पसंद का जिला मिला है। इस स्थानांतरण से शिक्षक संतुष्ट हैं और शिक्षकों ने पारदर्शी स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया है।

माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मौलिक शिक्षा विभाग द्वारा 2008 के

साप्ताहिक सूचना पत्र

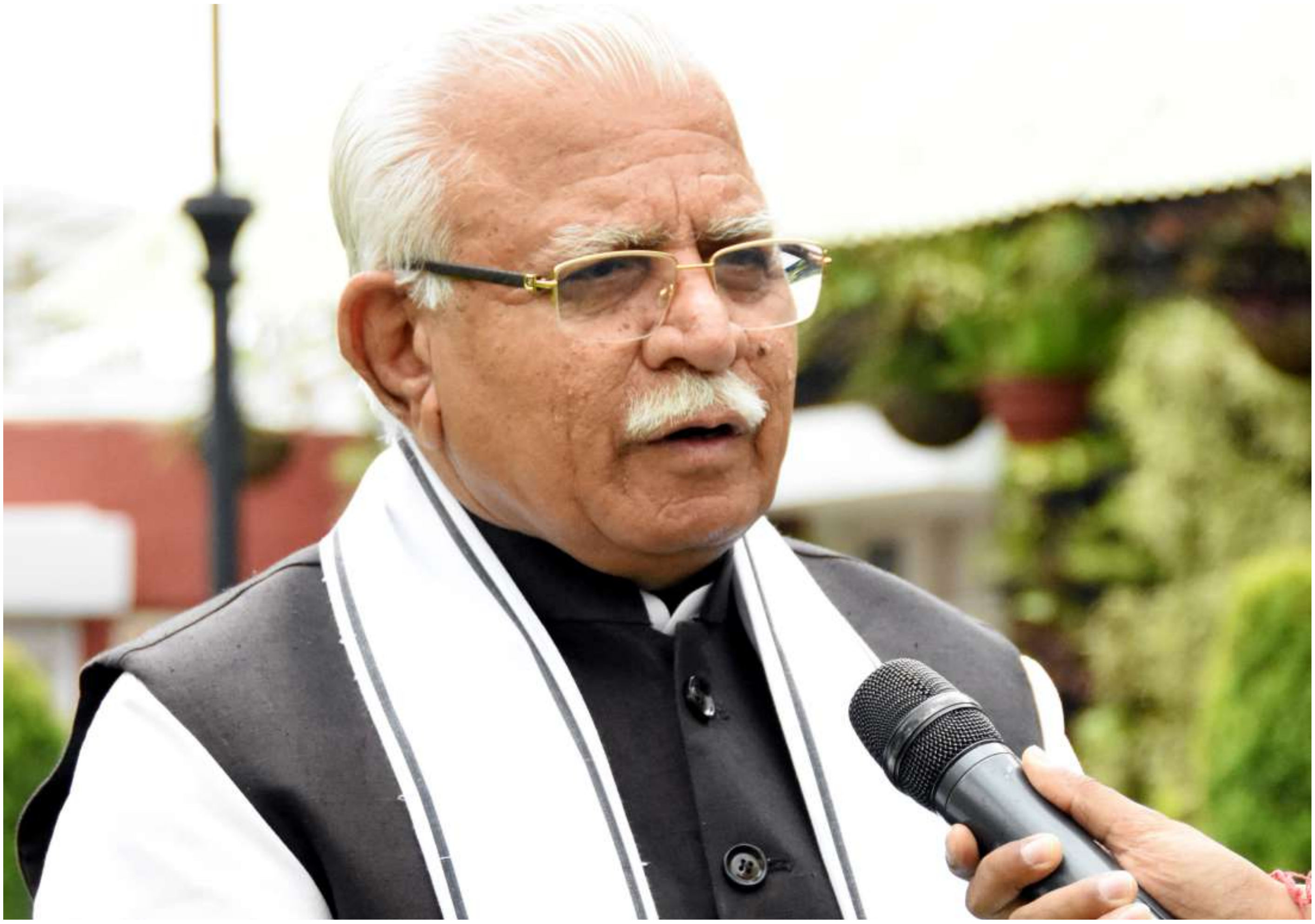

पीआरटी शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया भी 22 सितंबर से शुरू कर दी जाएगी। पीआरटी अपने विकल्प भरने सहित 22 सितंबर से स्वेच्छा से आवेदन कर सकेंगे। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने पीआरटी की जिलेवार और श्रेणीवार रिक्तियों को प्रसारित किया था ताकि शिक्षक अपनी पसंद के जिले का चयन कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी का विज़न है कि प्रदेश में शिक्षा के स्तर में वृद्धि हो और हर बच्चा श्रेष्ठ बने। यह तब होगा जब शिक्षक पूरे मन से बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके लिए शिक्षकों की परेशानियों को दूरा करना सरकार का कर्तव्य है।

दिल्ली के हरियाणा भवन में नारी शक्ति वंदन विधेयक पर महिलाओं से सीधा संवाद

(दिनांक 21.09.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज दिल्ली के हरियाणा भवन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंची महिलाओं से सीधा संवाद कर उन्होंने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन विधेयक लेकर आने पर माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया और सभी महिलाओं को इसके लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कदम की सराहना करता हूँ कि लम्बे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है जिससे बहनों की भागीदारी बढ़ेगी। महिलाएं इतनी खुश थी कि वे वहां बज रहे ढोल नगाड़ों पर नाचने लगी। उन्होंने 'मोदी है तो मुमकिन है' के नारे भी पूरे जोश के साथ लगाए। ये महिलाएं नये संसद भवन में पहुंचकर इस विधेयक के संबंध में चल रही चर्चा को देखने आई थी। सभी महिलाएं पहले दिल्ली के हरियाणा भवन में

साप्ताहिक सूचना पत्र

एकत्रित हुई, जहां से अलग–अलग समूहों में वे नये संसद भवन के लिए रवाना हुई। उन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक है, क्योंकि आज महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित होने के पश्चात राज्यसभा से पारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में पहले ही स्थानीय स्व–शासन संस्थाओं तथा पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नये संसद भवन में विशेष सत्र बुलाकर पहले ही दिन महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत करके ऐतिहासिक कार्य किया गया है। अब यह विधेयक राज्यसभा में भी पास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हमने महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्य किये हैं जिसमें से एक महत्वपूर्ण कार्य 22 जनवरी 2015 को पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरूआत थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उस समय लिगांनुपात 871 था, जो अब 923 से 926 तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि बेटियां व महिलाएं सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं, जिसका उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि एक शिक्षण संस्थान में आयोजित किये गये एक कार्यक्रम के दौरान स्वर्ण पदक विजेताओं की सूची में 20 में से 19 बेटियां थी।

मानेसर में फ्लिपकार्ट के क्षेत्रीय वितरण केंद्र का किया शिलान्यास व सोनीपत में किरयाना पूर्ति केंद्र का वर्चुअली शुभारंभ

(दिनांक 22.09.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज मानेसर में फ्लिपकार्ट के क्षेत्रीय वितरण केंद्र का शिलान्यास किया। साथ ही, वर्चुअल माध्यम से सोनीपत में किरयाना पूर्ति केंद्र का शुभारंभ किया। इन दोनों केन्द्रों से हरियाणा में निवेशकों की रूचि और बढ़ेगी। साथ ही युवाओं को रोजगार के भी अधिक अवसर मिलेंगे।

इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज हरियाणा के औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्र में दो नये मील पत्थर रखकर मुझे बड़े संतोष का अनुभव हो रहा है।

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि फ्लिपकार्ट द्वारा 285 एकड़ जमीन पर वेयरहाउसिंग और ट्रांसपोर्ट हब स्थापित किया जा रहा है। इसमें से 140 एकड़ जमीन पर 1389 करोड़ रुपये के निवेश से बनाया जाने वाला यह क्षेत्रीय वितरण केंद्र एशिया का सबसे बड़ा वितरण केन्द्र होगा। इसी प्रकार, सोनीपत में फ्लिपकार्ट के नये किरयाना पूर्ति केंद्र के माध्यम से रोजगार के लगभग 2,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर पैदा होंगे। साथ ही क्षेत्र के हजारों स्थानीय विक्रेताओं, एम.एस.एम.ई. और किसानों की पूरे देश के बाजार तक पहुंच बन जाएगी।

माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सम्बोधन में गुरुग्राम जिला में विकसित होने वाले ग्लोबल सिटी को क्षेत्र के विकास में नया अध्याय बताया।

एनपीआर और सीपीआर के बीच करीब एक हजार एकड़ भूमि पर विकसित होने वाले ग्लोबल सिटी के काम को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस

प्रोजेक्ट में एक लाख करोड़ रुपए का निवेश आने की प्रबल संभावना है। उन्होने कहा कि इस प्रकार के बड़े निवेश वर्ष 2024 तक भारत को 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने में अत्यंत कारगर सिद्ध होंगे, जिसमें हरियाणा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निरंतर निभा रहा है। उन्होंने कहा कि फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के सहयोग से हम अपने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित कर रहे हैं। इसी दिशा में गुरुग्राम में ग्लोबल स्मार्ट सिटी और मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसी प्रारंभिक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया है। नारनौल में 886 एकड़ क्षेत्र में एकीकृत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब विकसित किया जा रहा है। इसकी लागत 700 मिलियन अमरीकी डालर होगी। इसे दिल्ली– मुंबई इंडस्ट्रियल

कॉरिडोर प्रोजेक्ट के सहयोग से विकसित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि हम हरियाणा में उद्योग व निवेश के लिए प्रगतिशील व्यावसायिक माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति–2020 में व्यवसायों के लिए अनेक वित्तीय और नीतिगत प्रोत्साहनों का प्रावधान किया गया है। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गोदामों की ऊंचाई 15 मीटर से बढ़ाकर 21 मीटर और उन तक पहुंचने की दूरी 90 मीटर से बढ़ाकर 135 मीटर की है। यही नहीं, हमने महिला सशक्तिकरण के लिए वेयर हाउसिंग में महिलाओं को रात की पाली में काम करने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के अधिवासी कामगारों को तकनीकी प्रशिक्षण दिलाने के लिए लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग इकाइयों को प्रशिक्षण लागत के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जाती है, जो अधिकतम 10 हजार रुपये है। उन्होंने कहा कि

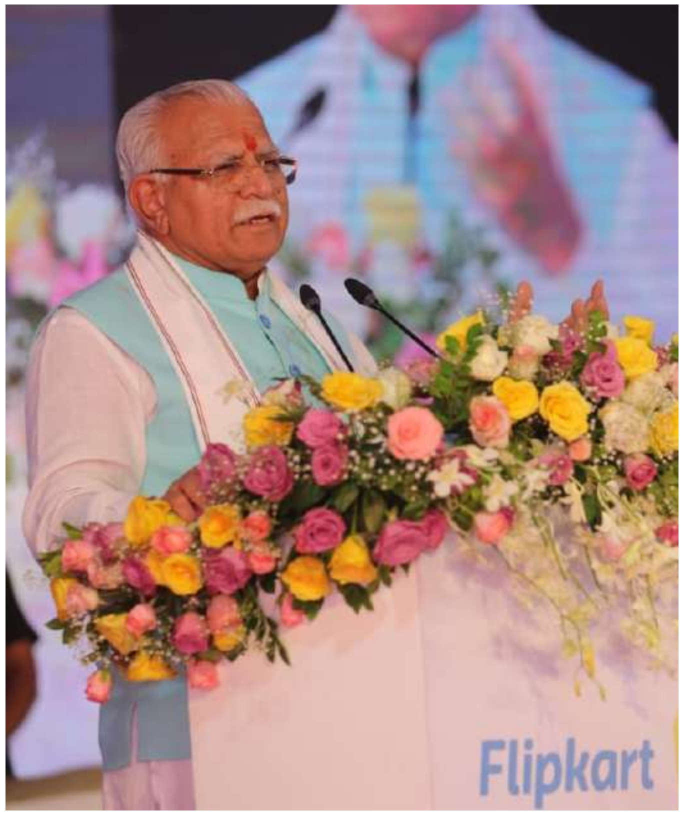

सफलता के लिए तीन मूल मंत्रों का जिक्र करना चाहूंगा ये लचीली आपूर्ति श्रृंखला के लिए मुख्य आधार स्तम्भ हैं। इन्हें 3–टी भी कहा जा सकता है। ये हैं ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी व टाईमलाइन। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ई–कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को सुझाव दिया कि आज हरियाणा में 55000 सेल्फ हेल्प ग्रुप से 5 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पादों को अपनी चेन में शामिल करें।

साप्ताहिक सूचना पत्र

वेद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के लिए प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण

(दिनांक 22.09.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज शुक्रवार को गुरुग्राम जिला के गांव मुबारिकपुर के समीप अशोक सिंघल वेद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के लिए प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रबंधन व जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ इस संस्थान के निर्माण से जुड़ी औपचारिकताओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। उन्होंने विश्वविद्यालय के लिए प्रस्तावित स्थल के आस–पास सड़क तंत्र को विकसित करने तथा निर्माण से संबंधित आवश्यक कार्यों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने में यह एक महत्वपूर्ण संस्थान होगा। ऐसे में इस संस्थान के निर्माण से जुड़ी सभी औपचारिकताएं समयबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएं। उन्होंने विश्वविद्यालय के भवन के मानचित्र का अवलोकन किया और संस्थान तक रोड़

क्नेक्टिविटी के लिए प्रस्तावित विकल्पों का स्वयं मौके पर जाकर निरीक्षण किया। उल्लेखनीय है कि अशोक सिंघल वेद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के लिए गांव मुबारिकपुर के समीप 40 एकड़ भू–खण्ड चिन्हित किया जा चुका है। इस विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय ज्ञान के साथ–साथ आधुनिक पद्धतियों पर आधारित कोर्सिज करवाएं जाएंगे। यह अपनी तरह का एक अनूठा शिक्षण संस्थान होगा।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशासनि सचिवों और जिला उपायुक्तों के साथ बैठक

(दिनांक 23.09.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशासनिक सचिवों और जिला उपायुक्तों के साथ हुई एक अहम बैठक में स्वामित्व योजना, लोक निर्माण विभाग की सडक़ों, मेरी फसल मेरा ब्योरा, मंडियों में फसल खरीद सुनिश्चित करने, मुख्यमंत्री घोषणाओं, मेरी माटी–मेरा देश, लिंगानुपात सहित सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं व कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। गांवों और शहरों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए तीन करम से अधिक चौड़ाई वाले सभी रास्तों को पक्का किया जाएगा। साथ ही, सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से स्वीकृत 1647 सड़कों में से 1632 सड़कों के टेंडर हो चुके हैं और 1378 सड़कों का काम आवंटित किया जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोक निर्माण विभाग द्वारा सडक़ों की मरम्मत व निर्माण कार्य को लेकर निर्देश दिए कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए विधायक को 25–25 करोड़ रुपये की राशि सडक़ों के निर्माण के लिए स्वीकृत की गई है। इन सडक़ों के टैंडर प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया और वर्क अलॉट करने में देरी न करें। उन्होंने 5 करम के रास्तों के कार्य के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि उपायुक्त इन रास्तों का सीमांकन सुनिश्चित करें ताकि समयबद्ध तरीके से इन पर काम शुरू हो सके। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि हाल ही में हुई बारिश के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों का सर्वे करवाएं और रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि कितनी सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता है। बैठक में बताया गया की ऐसी सड़कों के लिए 20 लाख रुपए की लागत की सड़क के कार्य एक्सीएन की कमेटी अपने स्तर पर करवा सकती है, इससे ऊपर के कार्य के लिए

साप्ताहिक सूचना पत्र

मुख्यालय के पास फाइल आएगी। उन्होंने उपायुक्तों को सड़कों की गुणवत्ता की निगरानी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उपायुक्तों को जनसंवाद कार्यक्रमों के दौरान प्राप्त प्रस्तावों और मांगों की बारीकी से निगरानी करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के समाधान में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और शिकायतों का समाधान तभी माना जाएगा, जब प्रतिवेदन देने वाला व्यक्ति संतुष्ट होगा। लोगों की संतुष्टि ही हमारा मुख्य ध्येय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जन संवाद कार्यक्रमों में कुछ शिकायतें, विशेष रूप से सरपंचों द्वारा उठाई गई शिकायतों की मौके पर ही घोषणा होती है। इसलिए प्रशासनिक सचिव और उपायुक्त जन संवाद के दौरान की गई घोषणाओं की एक व्यापक सूची

संकलित करें और इन्हें सीएम घोषणाओं में शामिल करें। उन्होंने कहा कि जनसंवाद पोर्टल पर उपायुक्तों और अतिरिक्त उपायुक्तों के कार्यालयों में प्राप्त सभी शिकायतों की भी बारीकी से निगरानी की जाए और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल की भी समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि पोर्टल पर दर्ज फसलों का कुछ डाटा मिसमैच है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि आगामी 2–3 दिनों में तुरंत टीमें गठित कर मौके पर जाकर चेक करें और डेटा को सत्यापित करें। इसके अलावा, किसानों को भी एक संदेश भेजा जाए कि वे भी तुरंत जिला कार्यालय में जाकर अपना डाटा सही करवा लें। उन्होंने कहा कि राज्य में 25 सितंबर से खरीद शुरू हो जाएगी, इसलिए सत्यापन का कार्य मिशन मोड में लेकर करना होगा।

उन्होंने मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को नियंत्रण कक्ष की स्थापना करने,

आवश्यक कंप्यूटर उपकरण और डेटा एंट्री ऑपरेटरों के साथ–साथ निर्बाध इंटरनेट सुविधा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये सभी व्यवस्थाएं मौजूदा मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से हरियाणा को 2.5 लाख मिट्रिक टन बाजरे की खरीद की अनुमति मिल चुकी है, इसलिए पड़ोसी राज्यों से बाजरे की स्मगलिंग की आशंका है। इसे देखते हुए जिला उपायुक्त कि पड़ोसी राज्यों से बाजरे की स्मगलिंग हो इसलिए सभी जिला उपायुक्त सभी संबंधित एजेंसियों के सहयोग से सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखें।

साप्ताहिक सूचना पत्र

प्ले वे स्कूलों के लाभार्थी अभिभावकों से सीधा संवाद

(दिनांक 23.09.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यहां एक विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्ले स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों के अभिभावकों से संवाद कर कहा कि नई शिक्षा नीति–2020 में नीहित 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे के संज्ञानात्मक और बौद्धिक क्षमता के विकास पर बल देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 4,000 प्ले–वे स्कूल खोलें हैं।

इन स्कूलों में लगभग 40 हजार बच्चों का दाखिला हुआ है। संवाद के दौरान बच्चों के माता पिता ने कहा कि सरकार द्वारा प्ले स्कूलों की जो सुविधा शुरू की गई है, उससे बच्चों को बहुत लाभ हो रहा है। पहले आंगनवाड़ियों में शिक्षा उतनी बेहतर नहीं होती थी लेकिन अब प्ले स्कूलों में खेल के साथ साथ बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दी जा रही है।

अभिभावकों ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इन स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन, खेल की सुविधाएं इत्यादि बहुत सुविधाएं मिल रही हैं। बच्चों के माता–पिता द्वारा दिए गए सुझावों पर

साप्ताहिक सूचना पत्र

माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां –जहां बच्चों की संख्या अधिक है, वहां कमरों की और व्यवस्था करवाई जाए या अन्य आंगनवाड़ियों को भी प्ले–वे स्कूल में अपग्रेड किया जाए। इसके लिए उपायुक्त अपने जिलों के प्ले–वे स्कूलों का सर्वे करवाएं, ताकि आवश्यकता –नुसार कार्रवाई की जा सके। क्यू1

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले के समय में घरों में आंगन और गलियां ही हमारा खेलकूद का स्थान होता था, लेकिन आजकल ऐसे स्कूल समाज की जरूरत बन गए हैं। आज के आधुनिक दौर में हर माता–पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसलिए लोग अपने बच्चों को प्ले स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजते हैं। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश के उज्ज्वल भविष्य की चिंता करते हुए 3 साल की आयु से ही बच्चों के लिए खेल–खेल में शिक्षा का प्रबंध किया है। इस जरूरत को जानते हुए निजी क्षेत्र में अनेक प्ले स्कूल खोले गये। उन्होंने कहा कि प्ले स्कूलों में बच्चों के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था हेतु हमने हर स्कूल में वाटर प्यूरीफायर लगाये हैं। बच्चों को तस्वीरें बहुत भाती हैं, इसलिए इन स्कूलों में वॉल पेंटिंग्स लगवाई गई हैं। उनके खेलने के लिए झूले और स्लाइडर भी लगवाए हैं। बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए हमने खिलौनों का विशेष प्रबंध किया है। इन प्ले स्कूलों में स्कूल की औपचारिक शिक्षा शुरू होने से पहले उन्हें स्कूल के लिए मानसिक रूप से तैयार करने और नैतिक संस्कार देने का काम किया जाता है।

उन्होंने सभी माता–पिता और अभिभावकों से अनुरोध किया कि आप अपने बच्चे को पूरा समय दें। आपको उनसे घुल–मिलकर उन्हें टाइम भी देना होगा, जब आप बच्चों को समय देंगे, तो वे न केवल भावनात्मक रूप से मजबूत होंगे. बल्कि उनका मानसिक विकास भी तेजी से होगा। इससे वे न केवल पढ़ाई–लिखाई में अव्वल होंगे, बल्कि वे ज्ञानवान और संस्कारवान बनेंगे।